भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1146

उत्तर देने की तारीख-10/12/2025

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग संबंधी

1146 # **श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हर वर्ष रैंकिंग्स (वरीयताक्रम) प्रकाशित करती है;

(ख) यदि हां**,** क्या इस वर्ष भी यह सूची प्रकाशित की गई है;

(ग) यदि हां, तो प्रथम/शीर्ष 100 संस्थानों में भारत की कितनी यूनिवर्सिटियों को स्थान मिला है; और

(घ) आगामी वर्षों में इस सूची में और ज़्यादा भारतीय यूनिवर्सिटियों को स्थान मिलना सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (डब्ल्यूयूआर), क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) द्वारा संकलित की जाती है और वार्षिक संस्करण में प्रकाशित की जाती है। वर्ष 2025 में जारी क्यूएस डब्ल्यूयूआर 2026 में 54 भारतीय संस्थानों को स्थान दिया गया है। यह भारत का अब तक का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, जो क्यूएस डब्ल्यूयूआर 2015 में 11 संस्थानों से बढ़कर क्यूएस डब्ल्यूयूआर 2026 में 54 हो गया है। आठ भारतीय संस्थानों को पहली बार रैंक किया गया है, जो इस वर्ष जी20 और वैश्विक स्तर दोनों पर किसी भी देश के लिए सबसे अधिक संख्या है।

उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का प्रावधान, अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, उद्योग-अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता

ने बदले में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सहित अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन में सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारत सरकार देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संस्थागत विकास, क्षमता निर्माण, अनुसंधान के लोकतंत्रीकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:

केंद्रीय वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बजटीय सहायता के अलावा, भारत सरकार उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)/प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) योजना के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा में सुधार के लिए तीन घटकों अर्थात "चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ाना", "विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान" और "बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू)" के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

इसके अलावा, अकादमिक, उद्योग और उद्यम निर्माण के अनुसंधान एवं विकास संचालित एकीकरण के उद्देश्य से, इन संस्थानों के आसपास अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए प्रमुख एचईआई में अनुसंधान पार्क स्थापित किए गए हैं। ये अनुसंधान पार्क उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए उद्योग से वित्त पोषित अनुसंधान की सुविधा प्रदान करते हैं। वर्ष 2014 से, सरकार ने 6 नए अनुसंधान पार्क स्थापित किए हैं, जिनमें से आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी गांधीनगर प्रत्येक में एक है।

भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2018-19 में 1650 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो (पीएमआरएफ) योजना शुरू की।

इसके अलावा, एचईआई में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, 6000 से अधिक एचईआई ने अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठों की स्थापना की है।

एनईपी 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) को गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च-स्तरीय कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।

सरकार ने एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा समन्वित एक राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से केंद्र या राज्य सरकार के प्रबंधन के तहत सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के सभी विषयों कें छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के विशाल समुदाय के लिए शोध पत्रिकाओं तक पहुंच का विस्तार करने के लिए ओएनओएस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 6300 से अधिक ऐसे संस्थान शामिल हैं। इस योजना के लिए 3 कैलेंडर वर्षों, 2025, 2026 और 2027 हेतु कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी श्रेणी प्रत्येक से 10 उच्चतर शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) का दर्जा प्रदान करने और उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभरने में सक्षम बनाने के लिए विश्व स्तरीय संस्थान योजना शुरू की। अब तक बारह संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें सार्वजनिक श्रेणी के 08 संस्थान और निजी श्रेणी के 04 संस्थान शामिल हैं। इस योजना के तहत केवल सार्वजनिक संस्थानों को ही धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 08 सार्वजनिक संस्थानों के लिए 6198.99 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि स्वीकृत की गई है।

इसके अलावा, अंतःविषय अनुसंधान करने, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों को विकसित करने और स्वास्थ्य, दीर्घकालिक शहरों और कृषि के तीन क्षेत्रों में मापनीय समाधान बनाने के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि में 990.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ स्वास्थ्य, दीर्घकालिक शहरों और कृषि के क्षेत्रों में तीन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना को मंजूरी दी है। आईआईटी मद्रास में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

“तकनीकी शिक्षा में बहु:विषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार” योजना को 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक सहित 275 तकनीकी संस्थानों में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) के अनुरूप अंत: क्षेपों को लागू करके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना है।

यह वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 की अवधि के लिए 4200 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय निहितार्थ के साथ एक 'केंद्रीय क्षेत्र की योजना' है।

*****